



भारतीय अर्थव्यवस्था, 2023

प्रलिस के लयः

मुद्रास्फीतः, यूकरेन युद्ध, तेल की कीमतें, ऋण संकट ।

मेन्स के लयः

भारतीय अर्थव्यवस्था, 2023 ।

चर्चा में क्यों?

भारतीय अर्थव्यवस्था के वर्ष 2022-23 में [सकल घरेलू उत्पाद \(Gross Domestic Product- GDP\)](#) में 6.9% की दर से वृद्धि दर्ज करने का अनुमान है, इसके अलावा [मुद्रास्फीतः](#) में कमी देखी जा रही है ।

- वर्ष 2020 में मुख्य घटना [कोवडि-19 महामारी](#) की पहली लहर के कारण देशव्यापी लॉकडाउन ने भारत की अर्थव्यवस्था के आकार को नरिधारति कथि ।
- वर्ष 2021 में [कोवडि की दूसरी भयानक लहर](#) थी जसिने भारतीय अर्थव्यवस्था और इसके उत्थान को आकार दथि ।
- वर्ष 2022 में [यूकरेन पर रूस के आक्रमण](#) ने बड़े पैमाने पर भारत की अर्थव्यवस्था का नरिधारण कथि गया ।
 - परणामस्वरूप मुद्रास्फीतः, रुपए की वनिमिय दर और भारत के वदिशी मुद्रा भंडार जैसे मुद्दे GDP वृद्धि की चतिओं से अधिक हावी हो गए ।

प्रमुख बदिः

- मुद्रास्फीतः**
 - वर्ष 2022 शुरू होने पर हेडलाइन खुदरा मुद्रास्फीतः पहले से ही 6% से ऊपर थी ।
 - यूकरेन पर रूस के आक्रमण के बाद मुद्रास्फीतः की स्थिति और खराब हो गई ।
 - अप्रैल 2022 में खुदरा मुद्रास्फीतः आठ साल के उच्चतम स्तर पर पहुँच गई । मई 2022 में जलदबाज़ी में बुलाई गई [मौद्रिक नीति समिति \(Monetary Policy Committee- MPC\)](#) की बैठक में RBI ने [रेपो रेट](#) बढ़ाने का फैसला कथि ।
 - यूएस और यूएस फेडरल रज़िर्व की कार्रवाइयों को वैश्विक मुद्रास्फीतः के प्रमुख कारकों के रूप में उद्धृत कथि गया था ।
- रुपए की वनिमिय दर और वदिशी मुद्रा भंडारः**
 - [कच्चे तेल की ऊँची कीमतों](#) के कारण भारत के कई व्यापक आर्थिक संकेतकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ।
 - वित्तीय वर्ष शुरू होते ही व्यापार घाटा बढ़ने लगा और भारत के [चालू खाता घाटा \(Current Account Deficit- CAD\)](#), [वदिशी मुद्रा भंडार](#) और [भुगतान संतुलन](#) के बारे में चिंताएँ होने लगीं ।
 - आखरिकार रुपया राजनीतिक रूप से संवेदनशील 80-टू-ए-डॉलर के नशान पर पहुँच गया लेकिन डॉलर के मुकाबले रुपया ही एकमात्र ऐसी मुद्रा नहीं थी, जो कमज़ोर हो रही थी । हालाँकि डॉलर भी यूरो से कमज़ोर था ।
- चौतरफा मौद्रिक सख्तीः**
 - वर्ष के मध्य तक दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने तरलता को कम करने और [मुद्रास्फीतः](#) को नयितरति करने के लयि ब्याज़ दरों में वृद्धि करना शुरू कर दथि ।
- GDP वृद्धि में कमीः**
 - मार्च 2022 में समाप्त हुए पछिले वित्तीय वर्ष (2021-22) में भारत की अर्थव्यवस्था में लगभग 9% की वृद्धि हुई थी ।
 - सितंबर 2022 में ब्रिटन को पछाड़कर भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया ।
 - भारत की वकिस दर पछिले वित्तीय वर्ष (2021-22) में लगभग 9% कम होकर चालू वर्ष (2022-23) में 7% से कम और अगले वित्तीय

वर्ष (2023-24) में लगभग 6% (या संभवतः कम) होने की उम्मीद है।

■ बजट, बेरोज़गारी और गरीबी:

- **केंद्रीय बजट** से पहले मुख्य चिंता यह पता लगाने की थी कि क्या सरकार देश में रोज़गार को बढ़ावा देने के लिये कोई योजना लेकर आ सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत में **कोविड से पहले भी ऐतिहासिक रूप से श्रम बाज़ार में उच्च स्तर का तनाव था तथा महामारी ने चिंता को और भी बढ़ा दिया।**
- बजट 2022-23 में भारत ने विकास का एक अच्छा चक्र शुरू करने के लिये पूंजीगत व्यय में उल्लेखनीय रूप से वृद्धि करने पर जोर दिया है।
- विशेषज्ञों ने तर्क दिया कि इस रणनीति के सामान्य समय में स्पष्ट लाभ हैं, हालाँकि भारत की अर्थव्यवस्था अभी भी कोविड से प्रभावित है, साथ ही यह स्पष्ट नहीं था कि रोज़गार को बढ़ावा देने के लिये बजट पर्याप्त होगा या नहीं।

वैश्विक आर्थिक आउटलुक, 2023

■ वृद्धि का पूर्वानुमान:

- भारतीय रज़िर्व बैंक ने '**अर्थव्यवस्था की स्थिति रिपोर्ट**' अद्यतन में 'डारकनेगि ग्लोबल आउटलुक/अंधेरा वैश्विक दृष्टिकोण' की चेतावनी दी है और बताया कि उभरती बाज़ार अर्थव्यवस्थाएँ (Emerging Market Economies- EME) 'अधिक कमज़ोर' प्रतीत होती हैं।
- वर्ष 2022 में वैश्विक विकास औसतन लगभग 3% रहने की उम्मीद एक सराहनीय उपलब्धि प्रतीत होती है।

■ मुद्रास्फीति:

- पछिले कुछ महीनों में वैश्विक खाद्य, ऊर्जा और अन्य वस्तुओं की कीमतें भले ही मामूली रूप से कम हुईं **हैंलेकिन मुद्रास्फीति अभी भी उच्च बनी हुई है।**
- **अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund- IMF)** के अनुसार, वैश्विक मुद्रास्फीति वर्ष 2022 में 8.8% से घटकर वर्ष 2023 में 6.5% की कमी के साथ वर्ष 2024 तक 4.1% होने का अनुमान है, हालाँकि अभी भी अधिकांश मानदंडों से उच्च है।
- अमेरिकी फ़ेडरल रज़िर्व को लगातार बढ़ती मुद्रास्फीति के परिणामस्वरूप वर्ष 2023 में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें कम-से-कम यह तथ्य नहीं है कि अमेरिकी श्रम बाज़ार अभी भी बढ़ रहा है और यह फ़ेड की मौद्रिक कठोरता के प्रभावों को नकारता है।

■ यूएस फ़ेड दर में वृद्धि का प्रभाव:

- हर बार जब फ़ेड नीतिगत दरें बढ़ाता है, तो अमेरिका और भारत जैसे देशों में ब्याज़ दरों के बीच का अंतर बढ़ जाता है, जिससे मुद्रा संबंधित लेन-देन व्यापार कम आकर्षक हो जाते हैं;
- अमेरिकी ऋण बाज़ारों में बढ़े हुए रटिर्न से **विकासशील बाज़ार इक्विटी में तेज़ी आ सकती है, इससे विदेशी निवेशकों के उत्साह में कमी आ सकती है।**
- यूएस को धन के बहरिवाह से मुद्रा बाज़ार संभावित रूप से प्रभावित होंगे; फ़ेड द्वारा नरिंतर दर में वृद्धि का मतलब है अमेरिका में विकास की गति भी कम होगी, जो वैश्विक विकास के लिये बुरी खबर हो सकती है, खासकर जब चीन एक नए कोविड प्रकोप का सामना कर रहा है।

भारतीय अर्थव्यवस्था, 2023 की संभावनाएँ:

■ सकारात्मक:

- भारतीय अर्थव्यवस्था में नक़िट भवषिय में स्थानीय कारकों की बदौलत तेज़ी से वृद्धि होने की उम्मीद है, जिनमें से **कुछ उच्च आवृत्ति संकेतकों** के रूप में परलक्षित होते हैं।
- **कॉर्पोरेट ऋण-से-GDP अनुपात लगभग 15 वर्षों में अपने सबसे नचिले बट्टि पर है, इसमें वगित पाँच वर्षों में काफी कमी आई है और बैंक बुक से ज़्यादातर पुराने खराब ऋणों को हटा दिया गया है।**
- ऋण-से-GDP अनुपात जतिना कम होगा, देश द्वारा अपने ऋण का भुगतान करने और डफ़ॉल्ट के अपने ज़ोखमि को कम करने की उतनी ही अधिक संभावना होगी, जिससे घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों में वित्तीय स्थिरता हो सकती है।
- इनपुट लागत के दबाव में कमी, कॉर्पोरेट बकिरी में वृद्धि और अचल परसिपत्तियों में निवेश में वृद्धि **केपेक्स चक्र में तेज़ी की शुरुआत है, जो संभावित रूप से भारत के विकास को गति देने में योगदान दे सकती है।**
- वगित आठ महीनों से बैंक ऋण दो अंकों में बढ़ रहा है, जो आंशिक रूप से **निवेश संबंधी ज़ोखमि (Investment Appetite)** में वृद्धि को दर्शाता है।
- यह देखते हुए कि **चीन कम कुशल, अकुशल श्रम, जैसे- कपड़ा, जूते, चमड़ा और चीनी मट्टि की वस्तुओं की आवश्यकता वाले निरिमाण कषेत्रों को कम महत्त्व दे रहा है** अतः भारत के पास इससे लाभ उठाने का एक मौका है, अधिकांश बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा **चीन-प्लस-वन रणनीति** का उपयोग एक अवसर प्रस्तुत कर सकता है।
- **समग्र GDP विकास में कृषि की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है, रबी** की अच्छी उत्पादकता को देखते हुए उच्च समर्थन मूल्य के साथ गेहूँ उत्पादन, पर्याप्त जलाशय स्तर और सहायक जलवायु कारकों के साथ कृषि कषेत्र में अच्छी संभावनाएँ देखि रही हैं।

■ चिंता का विषय:

- यूक्रेन युद्ध के जारी रहने से भारत के सबसे बड़े निर्यात बाज़ार यूरोपीय संघ में ऊर्जा से जुड़ी मंदी का खतरा है।
- फेड की दर वृद्धि में वरिष्ठ वर्ष की दूसरी छमाही तक संभव नहीं है क्योंकि अमेरिका घटती मुद्रास्फीति के दबाव से जूझ रहा है।
- वर्ष 2023 के लिये बढ़ते **संरक्षणवाद**, एक **वि-वैश्वीकरण-वरोधी आंदोलन** और **आर्थिक वखिंडन** संबंधी संभावनाएँ जाहिर की गई हैं, जो विशेषकर भारत जैसे देशों के लिये अस्थिर हैं तथा विकास के महत्त्वपूर्ण कारक के रूप में निर्यात का उपयोग करने हेतु उत्सुक हैं।
 - यह देखते हुए कि ठोस निर्यात वृद्धि के बिना एक दशक तक विश्व के किसी भी देश में 7% से अधिक की वृद्धि नहीं देखी गई है, **संरक्षणवादी प्रवृत्तिका वसितार उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिये प्रमुख बाधा है।**
- भारत में **निर्माण उद्योग में स्थिरता संबंधी समस्या है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक** (Index of Industrial Production- IIP) द्वारा मापा गया कारखाना उत्पादन अक्टूबर जैसे त्रयोहारी महीने में 26 महीने के नचिले स्तर पर आ गया। अक्टूबर में मुख्य क्षेत्र की वृद्धि महज 0.1% थी, जो कि 20 महीनों में सबसे कम है। इस कारण **वशिलेकों द्वारा अगले वित्त वर्ष में भारत के विकास में तेज़ी से गिरावट आने संबंधी अनुमान लगाए जा रहे हैं।**
- **कृषमता उपयोग**, संभावित उत्पादन के लिये वास्तविक उत्पादन का अनुपात है जिसे सामान्य परिस्थितियों में उत्पादित किया जा सकता है, में मामूली वृद्धि दर्ज की गई है जो 75% के नशान (Mark) पर बनी रहती है।
 - जब तक यह **नरिंतर रूप से नहीं बढ़ता है, तब तक नजिी नविश में प्रत्यक्ष रूप से वृद्धि होने की संभावना नहीं है।**
- **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** फर्मों के बीच समस्या बनी हुई है जो औद्योगिक सुधार में गहरे अंतर को दर्शाता है जहाँ बड़ी कंपनियाँ छोटी कंपनियों की तुलना में कहीं बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं।
- राज्यों का **पूंजीगत व्यय उतना मज़बूत नहीं है।** आमतौर पर राज्यों द्वारा किये गए नविश का गुणक प्रभाव अधिक होता है।
- देश के सकल घरेलू उत्पाद की 4% **आयातति ऊर्जा पर भारत की नरिभरता एक चुनौती है जो भुगतान संतुलन के पक्ष में दिखाई देती है।** वित्त वर्ष 2023 के लिये 3% से अधिक का चालू खाता घाटा अनुमानित है।
- कृषि उत्पादन में उछाल के बावजूद सतिंबर में लगातार नौवें महीने ग्रामीण मज़दूरी में कमी आई, जो कि आंतरिक क्षेत्रों में व्याप्त संकट की ओर इशारा करती है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न:

प्रश्न. कसिी देश के सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में कर में कमी नमिनलखिति में से कसिको दर्शाती है? (2015)

1. धीमी आर्थिक विकास दर
2. राष्ट्रीय आय का कम न्यायसंगत वितरण

नीचे दयि गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनयि:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (a)

व्याख्या:

- कर GDP अनुपात कसिी देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के सापेक्ष उसके कर राजस्व का अनुपात है। उदाहरण के लिये यदि भारत का टैक्स-टू-GDP अनुपात 20% है, तो इसका मतलब है कि सरकार को अपने सकल घरेलू उत्पाद का 20% कर योगदान के रूप में मलित है।
- कर GDP अनुपात का उपयोग वर्ष-दर-वर्ष कर प्राप्तियों की तुलना करने के लिये किया जाता है। चूँकि कर आर्थिक गतिविधि से संबंधित है, इसलिये अनुपात अपेक्षाकृत स्थिर रहना चाहिये। जब सकल घरेलू उत्पाद (GDP) बढ़ता है, तो कर राजस्व में भी वृद्धि होनी चाहिये।
- आर्थिक मंदी के परिणामस्वरूप विकास की दर कम होती है, जहाँ आमतौर पर बेरोज़गारी बढ़ती है और उपभोक्ता खर्च घटता है। नतीजतन, टैक्स-टू-GDP अनुपात में गिरावट आती है। **अतः कथन 1 सही है।**
- राष्ट्रीय आय का असमान वितरण सीधे तौर पर GDP अनुपात में कर में कमी से संबंधित नहीं है।
- राष्ट्रीय आय और संसाधन आवंटन का समान वितरण आमतौर पर कसिी देश की आर्थिक योजना पर नरिभर करता है। **अतः कथन 2 सही नहीं है।**
- **अतः विकल्प (a) सही है।**

??????:

प्रश्न. क्या आप इस मत से सहमत हैं कि सकल घरेलू उत्पाद की स्थायी संवृद्धि तथा नमिन मुद्रास्फीति के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में है? अपने तर्कों के समर्थन में कारण दीजयि। (2019)

प्रश्न: क्या आप सहमत हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने हाल ही में V-आकार के पुनरुत्थान का अनुभव किया है? कारण सहति अपने उत्तर की पुष्टि

स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/prospect-of-indian-economy-in-2023>

